

रजिस्टर्ड नं० ल-33/एस० एम० 14/92.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 1 अक्तूबर, 1992/9 आश्विन, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

आवकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 सितम्बर, 1992

संख्या 1-12/73-ई० एण्ड टी०-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसा करना आवश्यक में अनिवार्य है,

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 74) की धारा 8 की उप-धारा (5) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से निदेश देते हैं कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत, निम्नलिखित नई औद्योगिक इकाइयों द्वारा हिमाचल प्रदेश में निर्मित माल के अन्तर्राज्यीय वापार या वाणिज्य के क्रम में किए गए विक्रय पर केन्द्रीय बिक्री कर देय

नहीं होगा, जो आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश और निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश के पास रजिस्ट्रीकृत है :—

- (i) कृषि-बागवानी उत्पाद पर आधारित उद्योग सिवाए शराब के कारखाने, आसवनियों, शराब के कारखाने (wineries) और बोतल भरने के संयंत्र जो फलों पर आधारित न हों (देसी शराब और भारत में बनाई विदेशी शराब दोनों के लिए) । केवल तब ही छूट दी जाएगी जब,—
- (क) जब इकाईयां, हिमाचल प्रदेश सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना संख्या 1-12/73-ई0 एवं टी0-III, तारीख 7 फरवरी, 1992 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से अभिप्राप्त विहित प्रारूप आर0 एम0-II में एक प्रमाण-पत्र सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारी के पास प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक फाइल करती है।
- (ii) जड़ी-बूटी उत्पाद पर आधारित उद्योग तथा सुगन्ध प्रसाधन (एरोमेटिक) उद्योग । (ख) यह छूट इस प्रकार की औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्पादन आरम्भ करने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए होगी :
- (iii) ऊन पर आधारित उद्योग (जिनमें अंगोरा ऊन भी सम्मिलित है) । परन्तु कम संख्या (V) के सामने उपर्युक्त इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक एसेम्बली इकाईयां और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इकाईयों के मामले में छूट केवल ऐसी इकाईयों को उपलब्ध होगी जिन्होंने 1-4-1985 के बाद और 31-3-1991 तक उत्पादन किया, और
- (iv) रेशम उत्पादन, और
- (V) इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक एसेम्बली इकाईयां और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इकाईयां नहीं हैं । (ग) इकाईयां जो हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, 1968 और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 और उनके तदधीन बनाए/जारी किए गए नियमों और अधिसूचनाओं के सभी उपबन्धों का अनुपालन करती हैं।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना में नई औद्योगिक इकाई से ऐसी औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है कि जो अप्रैल, 1991 के प्रथम दिवस को या उसके पश्चात् उत्पादन प्रारम्भ करती है और इसके अन्तर्गत ऐसी विद्यमान इकाई भी होगी जो विकास आयुक्त, लघु उद्योग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नए सिरे से रजिस्ट्रीकरण की पात्र होगी परन्तु कोई भी छोटी, मध्यम या बड़ी औद्योगिक इकाई जिसे पुनः स्थापन के परिणामस्वरूप, केवल स्वामित्व में परिवर्तन के कारण संविधान में परिवर्तन, पुनः ढांचा या विद्यमान औद्योगिक इकाई के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप गठित किया गया हो, इसके अन्तर्गत नहीं होगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

[Authoritative English text of this department notification No. 1-12/73 E&T-III, dated the 25th September, 1992, as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th September, 1992

No. 1-12/73-E&T-III.—Whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that it is necessary in the public interest so to do ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to direct that no tax shall be payable under the said Act in respect of the sale made in the course of Inter-State Trade or Commerce of the goods manufactured by the following new industrial units, in the State of Himachal Pradesh, which are registered with the Excise and Taxation Department, Himachal Pradesh and the Director of Industries, Himachal Pradesh, with immediate effect :—

(i) Agriculture-Horticulture Produce based industries, except Breweries, Distilleries, non-fruit based wineries, and Bottling Plants (both for Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor);

(ii) Herbal-produce based industries and Aromatic industries;

(iii) Wool-based industry (including Angora wool);

(iv) Sericulture; and

(v) Electronic industry excluding electronic Assembly Units and Computer Software Units.

The exemption shall be granted only when,—

(a) The units file by 30th April every year with the Assessing Authority concerned a certificate in Form R.M. II, prescribed by the Himachal Pradesh Government, Excise and Taxation Department Notification No. 1-12/73-E&T-III, dated the 7th February, 1992, obtained from the authority specified therein;

(b) The exemption will be available for a period of 10 years from the date of commencement of production by such industrial units:

Provided that in the case of Electronic industry excluding Electronic Assembly Units and Computer Software Units shown against serial No. (v) in which case the exemption will be available only to such units which came into production after 1-4-1985 and upto 31-3-1991; and

(c) the units comply with all provisions of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 and Central Sales Tax, 1956 and the rules and notifications framed/issued thereunder.

Explanation.—In this notification 'new industrial unit' means an industrial unit which commences production on or after first day of April, 1991 and will include any existing unit which is eligible to get fresh registration as per the guide-lines issued by the Development Commissioner, Small Scales Industries, Government of India, from time to time, but will not include any industrial unit, small, medium or large, which is formed as a result of re-establishment, mere change of ownership, change in the constitution, re-structuring or revival of an existing industrial unit.

By order,

Sd/-

Financial Commissioner-cum-Secretary.